



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938

No. 60]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली 17 मार्च, 2017

प्रकरण सं. ओ.आई. 17/2017

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फास्फोरस पेंटॉक्साइड या पी 205 के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 14/47/2016-डीजीएडी.—मै. संध्या डाइस एंड केमिकल लि. (जिसे आगे आवेदक/घरेलू उद्योग/याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण के लिए) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष पाटनरोधी जांच आरंभ करने और चीन जन.गण., (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फास्फोरस पेंटॉक्साइड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के विषय में पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और चूंकि, प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षति' और कथित पाटन तथा 'क्षति' के बीच सांयोगिक संबंध के पर्याप्त प्रमाण पाटनरोधी जांच को उचित ठहराने के लिए विद्यमान हैं, प्राधिकारी द्वारा, एतद्वारा, नियमावली के नियम 5 की शर्तों में कथित पाटन और घरेलू उद्योगों को परिणामिक क्षति, कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि लगाया जाता तो वह घरेलू उद्योग की 'क्षति' को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, के लिए जांच आरंभ कर दी गई है।

क. घरेलू उद्योग और स्थिति

3. याचिका भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग के रूप में मै. संध्या डाइस एंड केमिकल्स लि. द्वारा दायर की गई है।

4. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक कंपनी का उत्पादन घरेलू उत्पादन का 'प्रमुख भाग' ठहरता है क्योंकि यह देश में संबद्ध वस्तुओं की एकमात्र उत्पादक कंपनी है। अतः प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार अर्थों के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन पहले उल्लिखित नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में प्रचलित मानदंड को पूरा करता है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद 'फास्फोरस पेंटॉक्साइड' है।

6. पी205 को फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस (v) ऑक्साइड, फास्फोरिक अनहाइड्राक्साइड, टेट्राफास्फोरस डेकाऑक्साइड, टेट्रा फास्फोरस डेकोक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक श्वेत, माइक्रोक्रीस्टोलिन, हल्के भार वाला पाउडर है जिसे ऑक्सीजन के आधिक्य में प्राकृतिक फास्फोरस के ज्वलन द्वारा उत्पादित किया जाता है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड आर्थोफास्फोरिक एसिड, H_3POH का अनहाइड्राइड है। यह अत्यधिक आर्द्रता ग्राही है और जल द्वारा माध्यस्थों के जरिए H_3PO_4 में परिवर्तित हो जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। पीयूसी का सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-28 के अंतर्गत एक विशिष्ट एच कोड 29091000 है। सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और यह इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

8. आयात संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने सौदावार डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों का सहारा लिया है।

ग. समान वस्तु

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामान और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सामान के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, मूल्य निर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण तुलनीय है। उपभोक्ता दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकता है और प्रयोग कर भी रहा है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और अतः दोनों को नियमावली के तहत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों/राज्य क्षेत्रों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में मानते हैं।

घ. जांच किए जाने वाले देश

10. वर्तमान जांच चीन जन.गण.(जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

ड. सामान्य मूल्य

11. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू मूल्यों पर सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना के अभाव में संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान उत्पादन लागत, उन देशों में कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए, उत्पादन लागत, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और विधिवत रूप से समायोजित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय जमा तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए लगाया गया है।

च. निर्यात मूल्य

12. याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य का एक द्वितीय स्रोत, आईबीआईएस से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर आधारित संबद्ध देश से भारांशित औसत आयात मूल्य के आधार पर दावा किया है। मूल्य समायोजन का दावा समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए बैंक प्रभार के आधार पर किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य की कारखानागत स्तर पर निर्यात मूल्य के साथ तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात मूल्य से अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं को पाटित किया जा रहा है और पाटन मार्जिन उक्त न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

14. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप और उत्पादन और खपत के संबंध में कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री तथा उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, माल सूची में गिरावट के रूप में परिणामी विपरीत प्रभाव के संबंध में प्रमाण उपलब्ध कराए हैं। पाटनरोधी जांच को आरंभ किए जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा वहन की जा रही “महत्वपूर्ण क्षति” के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

15. याचिकाकर्ता द्वारा जांच की अवधि (पी ओ आई) जुलाई, 2015-जून, 2016 (12 महीने) प्रस्तावित की गई है। तथापि, प्राधिकारी को अधिक अद्यतन आंकड़ों के आधार पर जरूरी विश्लेषण करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकारी ने जांच की अवधि जुलाई, 2015 से 30 सितंबर, 2016 (15 महीने) निर्धारित की है। हालांकि, क्षति जांच अवधि में 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद के साथ संबद्ध भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में व निर्धारित तरीके से प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत कर सकें और अपने विचार नीचे दिए गए पतों पर प्राधिकारी को भेज सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र और तरीके में नीचे दी गई समय सीमा के भीतर भेज सकता है।

ठ. समय-सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई जानकारी और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से अनधिक ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी तक पहुंच सके।

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज करा सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे तत्कालीन मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और अपनी प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों को और पाटनरोधी उपायों को लागू करने की आवश्यकता के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन के संबंध में अपनी टिप्पणियों को इस जांच के आरंभ होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर दायर करें।

ड. अगोपनीयता आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के प्रत्युत्तर/प्रस्तुतियों के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो पृथक सैटों में प्रस्तुत करना होगा (क) गोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) और (ख) अगोपनीय के रूप में चिन्हित अन्य सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित)। प्रस्तुत की गई सारी जानकारी के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी भाग पर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करानी होंगी।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचनाप्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/अथवा ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद, प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ण. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)**New Delhi, the 17th March, 2017**Case No. OI 17/2017****INITIATION NOTIFICATION**

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Phosphorus Pentoxide or P2O5, originating in or exported from China PR

F.NO 14/47/2016-DGAD.— M/s Sandhya Dyes & Chemicals Ltd (hereinafter referred to as the applicant/domestic industry/petitioner) have filed an application/petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of Phosphorus Pentoxide (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the quantum of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

A. Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed M/s Sandhya Dyes & Chemicals Ltd by as the domestic industry of the subject goods in India.
4. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes "a major proportion" of the domestic production since it is the sole producer of the subject goods in the Country. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

B. Product under Consideration

5. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Phosphorous Pentoxide".
6. P2O5 is also known as Diphosphorous Pentoxide, Phosphorus(V) oxide, Phosphoric anhydride, Tetraphosphorus is decaoxide, Tetraphosphorus decoxide. Phosphorus pentoxide is a white, microcrystalline, light weight powder which is produced by the combustion of elemental phosphorus in an excess of oxygen. Phosphorus pentoxide is the anhydride of orthophosphoric acid, H3PO4. It is very hygroscopic and is converted by water to H3PO4 via intermediates.
7. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act. The PUC has a specific HS code 28091000 under Chapter 28 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.
8. For the purpose of analyzing the imports data, the Authority has relied upon transaction wise DGCI&S data.

C. Like Article

9. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use

and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country/territory.

D. Country involved

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR (referred to as the "subject country").

E. Normal Value

11. The petitioners have submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries the Normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production; taking into account prevailing international prices of raw materials and cost of utilities in subject countries, conversion costs of the domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

F. Export Price

12. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from subject country based on the transaction-wise import data obtained from a secondary source, IBIS. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, Marine insurance, Commission, Inland Freight expenses, Port expenses and Bank charges to arrive at the net export price at ex-factory level.

G. Dumping Margin

13. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

H. Injury and Casual Link

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, inventories. There is sufficient prima facie evidence of the 'material injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

I. Period of Investigation

15. The Period of Investigation (POI) proposed by the applicant is from July 2015 – June 2016 (12 months) However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority has fixed the POI as 1st July 2015 to 30th September 2016 (15 Months). The injury investigation period will however cover the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and period of investigation.

J. Submission of information

16. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

K. Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation

L. Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.
22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

M. Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

N. Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority